





प्राक्कथन

मेरे प्रिय हरियाणावासियों !

कर्म के मार्ग पर जब अनवरत चलते रहने का संकल्प लिया हो तो फिर कालखंड या समय की गणना नहीं होती। मगर कुछ मोड़ आते हैं जहां थोड़ा पीछे भी नजर दौड़ानी होती है।

हरियाणा के कर्मनिष्ठ लोगों में गौरव का यह भाव सदा बना रहता है कि वे वैदिक ऋचाओं एवं श्रीमद्भगवद् गीता की पुण्यधरा के वासी हैं। इसी धरा पर अनेक संतों, गुरुओं की वाणी व सरस्वती की लहरों ने यहां के आध्यात्मिक परिवेश को समृद्ध बनाया है। वर्तमान युग में यह प्रदेश आर्थिक-सामाजिक क्षेत्र में तेजी से आ रहे बदलावों का साक्षी रहा है।

लगभग 2500 दिन पूर्व 'जन हित' एवं 'हर हित' का संकल्प लेकर हमने जन सेवा की बागड़ोर संभाली थी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का अन्त्योदय-दर्शन, अटल जी द्वारा प्रशस्त समानता का मार्ग और प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी द्वारा समय-समय पर दिए जा रहे विकास मंत्र 'सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास' हमारे मार्गदर्शक भी हैं और नई नीतियों का केन्द्र बिन्दु भी हैं।

पिछले 2500 दिनों में हम सबने मिलकर प्रयास किया है कि लोक प्रशासन की प्रणाली भी समय की मांग के अनुरूप बदलें। हम जाति, वर्ग व क्षेत्र की तंग गलियों से बाहर आए। प्रदेश के प्रगतिशील लोग बदलावों की ताजा बायर में सांस लेते हुए परंपरा व आधुनिकता के बीच एक सुदृढ़ पुल का निर्माण करते हुए आगे बढ़े हैं।

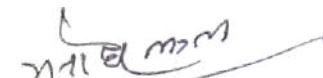
आज जब हम भारतीय स्वतंत्रता का 'अमृत महोत्सव' मना रहे हैं तो हम प्रदेश के चहुंमुखी विकास के साथ-साथ स्वाभिमान, स्वायत्ता, संरक्षण, शिक्षा, स्वावलंबन, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वामित्व, समाधान, और सुशासन को नए आयाम देने पर गर्व करते हैं।

इन 2500 दिनों की कर्म-यात्रा में अब तक की उपलब्धियों का एक संक्षिप्त लेखा-जोखा इस पुस्तिका में दिया गया है। मगर अभी अनेक ऐसे लक्ष्य हैं जो निर्धारित हो चुके हैं और इन पर आने वाले समय में तेजी के साथ क्रियान्वयन के लिए हमारी सरकार संकल्पबद्ध है। मेरा यह संकल्प है कि आने वाले समय में हमारा यह प्रदेश, पूरे देश में विकास की दृष्टि से प्रथम स्थान पर रहे। आपकी हर पावन कसौटी पर खरा उतरने के प्रयास में हम निरन्तर लगे रहेंगे। हम सब हरियाणा एक - हरियाणवी एक के संकल्प-सूत्र के साथ आगे बढ़ते रहेंगे।

जय हरियाणा, जय हिंद !

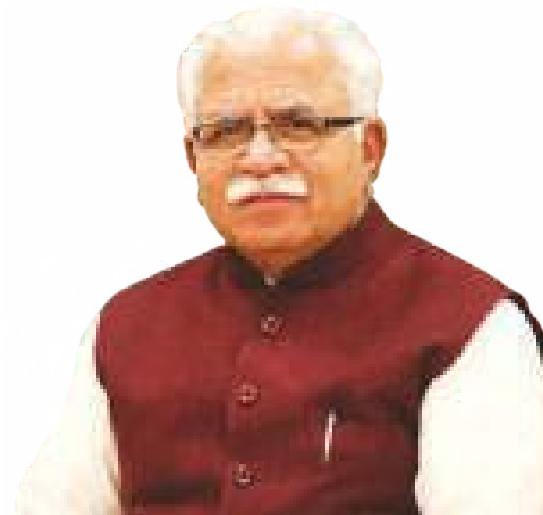
29 अगस्त 2021

आपका



श्री मनोहर लाल

मुख्यमंत्री



कैबिनेट मंत्री



श्री दुष्यंत चौटाला
उप सुरक्षमंत्री

कमरा नं. 40/5, सचिवालय
दूरभाष नं. 0172-2740212



श्री अनिल विज
गृह मंत्री

कमरा नं. 32/8, सचिवालय
दूरभाष नं. 0172-2740793



श्री कविंदर पाल
शिक्षा मंत्री

कमरा नं. 34/8, सचिवालय
दूरभाष नं. 0172-2740010



श्री मूलचंद शर्मा
परिवहन मंत्री

कमरा नं. 49/8, सचिवालय
दूरभाष नं. 0172-2740157



श्री रंजीत सिंह
विद्युत मंत्री

कमरा नं. 39/8, सचिवालय
दूरभाष नं. 0172-2740231



श्री जय प्रकाश दलाल
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री

कमरा नं. 42/6, सचिवालय
दूरभाष नं. 0172-2743709



श्री बनवारी लाल
सहकारिता मंत्री

कमरा नं. 24/8, सचिवालय
दूरभाष नं. 0172-2740906

राज्य मंत्री



श्री ओम प्रकाश यादव
सामाजिक न्याय एवं
अधिकारिता राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार

कमरा नं. 43-सी/8, सचिवालय
दूरभाष नं. 0172-2740867



श्रीमती कमलेश ढांडा
महिला एवं बाल विकास,
राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार

कमरा नं. 31/8, सचिवालय
दूरभाष नं. 0172-2740358



श्री अनूप धानक
पुरातत्व एवं संग्रहालय,
राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार

कमरा नं. 47/8 सचिवालय
दूरभाष नं. 0172-2740195



श्री संदीप सिंह
खेल एवं युवा मामले,
राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार

कमरा नं. 30/9, सचिवालय
दूरभाष नं. 0172-2740892





अंत्योदय



तराय
कार्यक्रम



स्थान अन्जन योजना

विभाग विश्राम गृह, पंचकूला

सिंह, रक्षा मंत्री, भारत सरकार

लाल, मुख्यमंत्री, हरियाणा

टाला, उप मुख्यमंत्री, हरियाणा

अधिसंविति:

श्री रतन लाल कटारिया

सामैदू, लोकसभा क्षेत्र, अंब

श्री राशन



5 किलो गेहूं
पात्र व्यक्ति प्रति म

मुफ्त



'मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान अभियान' के प्रथम चरण में सबसे गरीब 2 लाख परिवारों की पहचान करके उनकी न्यूनतम वार्षिक आय 1 लाख रुपये करने का लक्ष्य।

अधिक परिवारों को लाभ देने के लिए बी.पी.एल. की वार्षिक आय सीमा 1.20 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.80 लाख रुपये की।

'मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना' के तहत हर बी.पी.एल. परिवार को विशेष आर्थिक पैकेज और जीवन सुरक्षा बीमा व पेंशन स्कीमों के प्रीमियम का भुगतान।

'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्वयोजना' के तहत गरीबों को मुफ्त राशन।

'अंत्योदय आहार योजना' के तहत श्रमिकों व गरीबों को सस्ता भोजन देने वाले भोजनालय खोले।





सभी तरह की सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाकर 2500 रुपये मासिक की।

हरियाणा भवन निर्माण और अन्य सन्त्रिमाण बोर्ड के 60 वर्ष से अधिक आयु के श्रमिकों को 2750 रुपये मासिक पेंशन

'आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना' के तहत 27 लाख ग्रामीण परिवारों का सालाना 5 लाख रुपये तक मुफ्त इलाज।

'प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना' के तहत रेहड़ी-पटरी वालों को अपना काम शुरू करने के लिए 10 हजार रुपये तक का ब्याज रहित ऋण।

विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों द्वारा चलाई जा रही सभी आवास योजनाओं को एक छत के नीचे लाने के लिए 'सभी के लिए आवास' विभाग का गठन।





'डॉ. बी.आर. अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना' में बी.पी.एल. परिवारों को मकान-मरम्मत के लिए 80,000 रुपये की सहायता।

'प्रधानमंत्री आवास योजना' के तहत ग्रीबों के लिए 75 हजार मकान बनाये गये। दीनदयाल जन आवास योजना के तहत 1.25 लाख मकान बनाने का लक्ष्य।

ग्रीब परिवारों की बेटियों के विवाह पर **'मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना'** के तहत 51,000 रुपये तक की शगुन राशि।

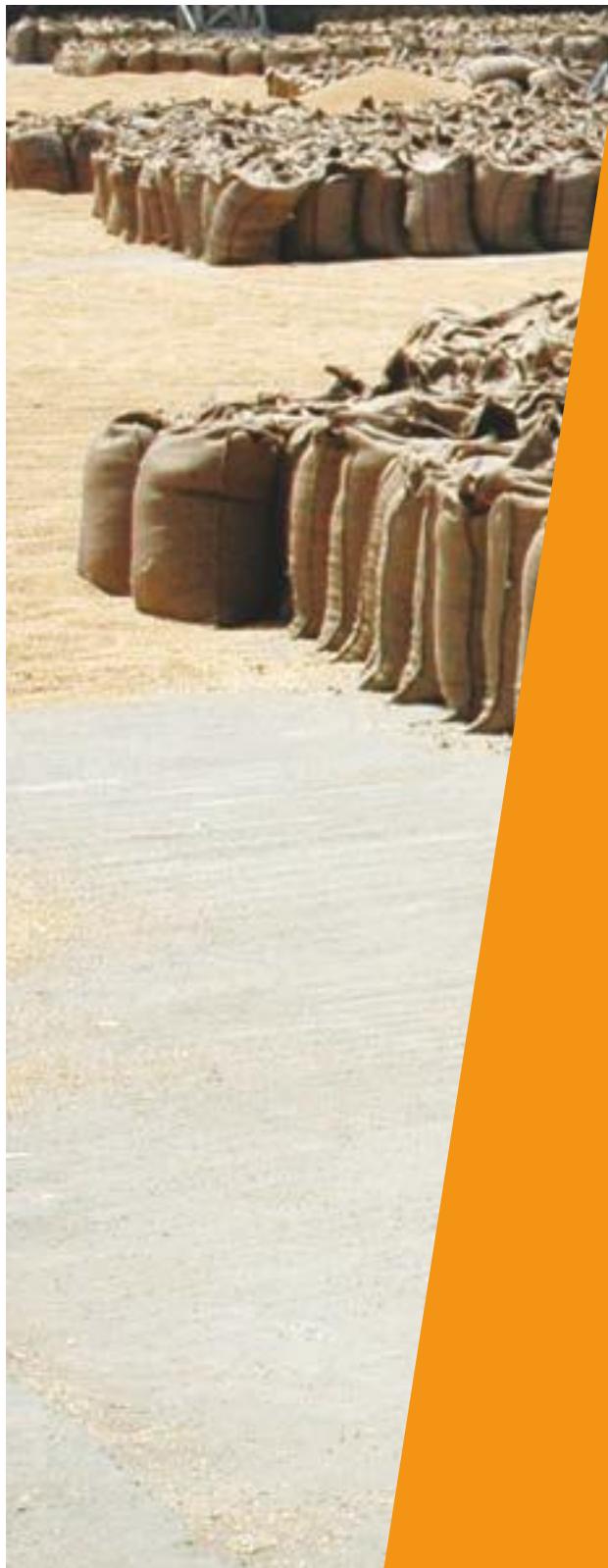
अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को 22,000 रुपये की कानूनी सहायता।

आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के विद्यार्थियों को उच्चतर शिक्षा में 10 प्रतिशत आरक्षण।

कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन के दौरान ऑपरेशन संवेदना के तहत साढ़े चार लाख प्रवासी श्रमिकों को सरकार के खर्च पर उनके घृह राज्यों में पहुँचाया।

सरकार का ध्येय है कि हरियाणा के हर परिवार की वार्षिक न्यूनतम आय 1.80 लाख रुपये हो।

किसान कल्याण







बीज से बाजार तक किसान के साथ सरकार।

न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सबसे ज्यादा **11 फसलों** की खरीद करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य।

ग्रन्ति का देश में सर्वाधिक भाव।

फसलों का भुगतान **72 घंटे** के भीतर सीधा किसानों के खातों में।

पिछले **2500 दिनों** में विभिन्न योजनाओं के तहत लगभग 50 लाख किसानों को लगभग 11 हजार करोड़ रुपये का सीधा नकद लाभ।

खरीद को सुव्यवस्थित बनाने के लिए '**मेरी फसल-मेरा ब्यौरा**' पोर्टल शुरू।

सब्जियों व फलों के लिए भावांतर भरपाई योजना।

फसल विविधिकरण और जल संरक्षण के लिए "मेरा पानी-मेरी विरासत" योजना।

बागवानी क्षेत्र को दोगुणाव उत्पादन को तीन गुणा करने के लिए वर्ष 2030 तक का बागवानी विज्ञन तैयार।

हर खेत-स्वस्थ खेत अभियान के तहत लगभग 87 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित।

76 मृदा एवं जल परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित।

Earn While you Learn Scheme के तहत विद्यार्थियों को मृदा एवं जल जांच कर पढ़ाई के साथ अतिरिक्त आय का अवसर।



लगभग 500 किसान उत्पादक समूहों (FPO) से 77 हजार किसानों को जोड़ा गया तथा 1000 किसान उत्पादक समूह बनाने का लक्ष्य।

किसान अब 5000 रुपये की स्टाम्प ड्यूटी देकर अपनी जमीन की अदला-बदली कर सकेंगे।

बैंकों से किसानों द्वारा लेनदेन पर स्टाम्प फीस कम।

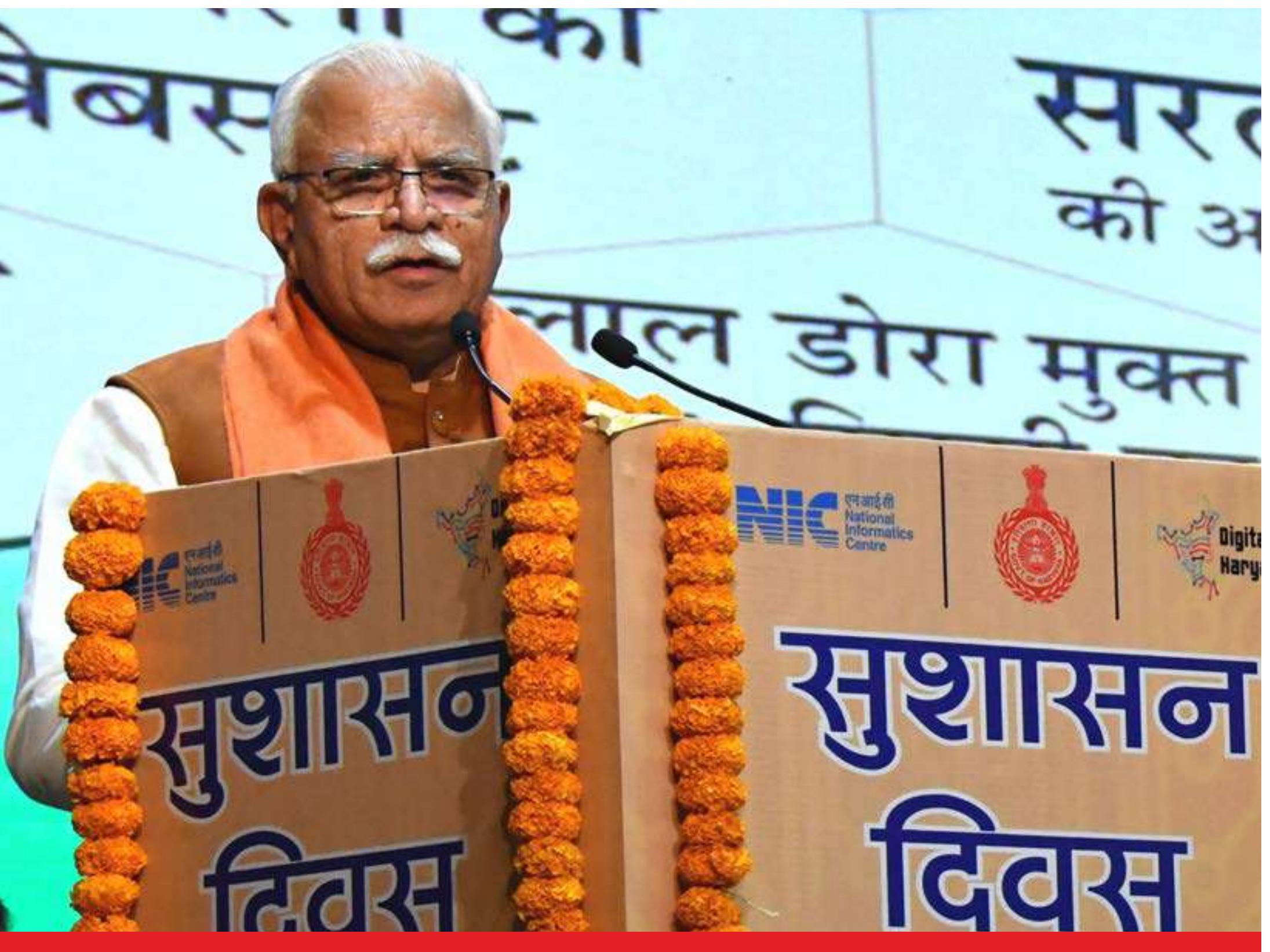
छोटे किसानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने के लिए 'प्रधानमंत्री किसान समान निधि योजना'।

किसान मित्र योजना के तहत राज्य में 1000 किसान एटीएम स्थापित किए जा रहे।

एकमुश्ति निपटन योजना और सरचार्ज माफी योजना के तहत किसानों को ऋणों में राहत दी।

प्राकृतिक आपदा से फसल खराब होने पर मदद के लिए 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना'।

पशुपालकों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर 'पशुधन क्रेडिट कार्ड योजना'।



सुशासन
दिवस

सुशासन
दिवस

विवरण का

सरका
की अ

लाल डोरा मुक्त

NIC
National
Informatics
Centre

NIC
राष्ट्रीय
National
Informatics
Centre

Digital
Hary

व्यवस्था परिवर्तन से सुशासन



सुशासन के प्रणेता पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिवस 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है।

वर्ष 2020 को सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाया और 2021 को सुशासन परिणाम वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है।

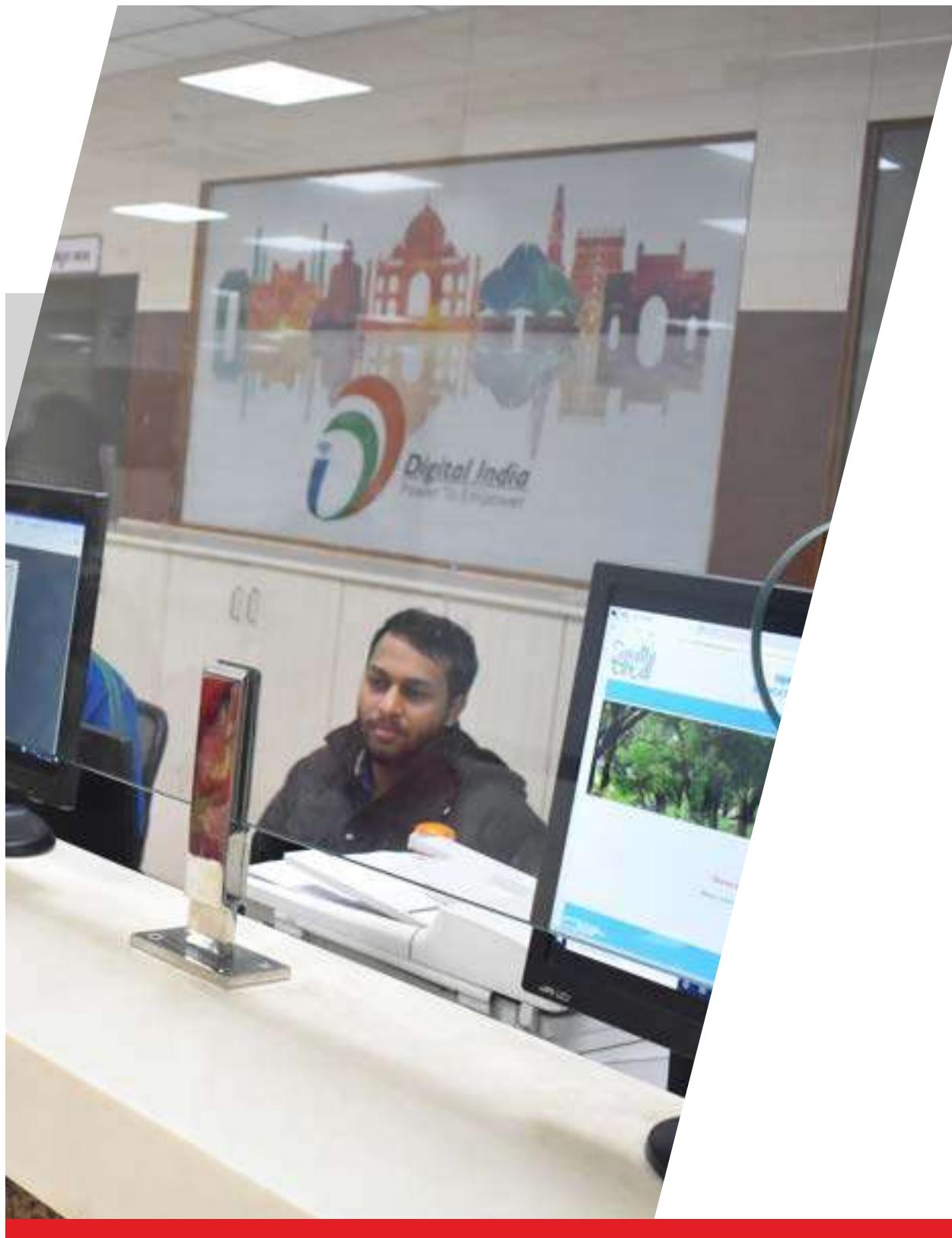
संकट के समय तुरंत मदद प्रदान करने के लिए आई.टी. का उपयोग कर सभी आपातकालीन सेवाओं को मिलाकर 'हरियाणा-112 आपातकालीन त्वरित सहायता प्रणाली' संचालित।

परिवार पहचान पत्र के माध्यम से सरकारी योजनाओं और सेवाओं का घर बैठे लाभ। कार्यालयों के चक्कर काटने से छुटकारा।

अंत्योदय सरल पोर्टल पर 42 विभागों की 547 सेवाएं और योजनाएं ऑनलाइन उपलब्ध। इस परियोजना को फरवरी 2020 में आयोजित 23वें राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन में गोल्ड अवार्ड मिला।

योग्यता के आधार पर नौकरियां देकर खर्ची-पर्ची सिस्टम बंद किया, स्थानांतरण को ऑनलाइन कर तबादला उद्योग बंद किया। आई.टी. का उपयोग कर सरकारी कामकाज में दलाली करने वाले की दुकानें बंद करवाईं।





सरकारी खजाने से नागरिकों को सहायता देने वाली सैकड़ों स्कीमों को डी.बी.टी.से जोड़ा और पैसा सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा करवाया। इसके लिए प्रदेश को **स्मार्ट गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड** मिला।

जमीनों की रजिस्ट्री में गडबड़ी को रोकने के लिए विभिन्न विभागों, बोर्डों व निगमों आदि के अनापत्ति प्रमाण-पत्र ऑनलाइन जारी करने शुरू किये।

भूमि विवादों के निपटान में **रिमांड** एक बड़ी बाधा थी जो भ्रष्टाचार की जननी थी। **रिमांड की प्रथा** को खत्म किया।

सी.एल.यू. को पूरी तरह ऑनलाइन किया।

ई-पंजीकरण प्रणाली के तहत रजिस्ट्री के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट।

सरकारी कामकाज में तेजी लाने और फाइलों के शीघ्र निपटान के लिए **ई-ऑफिस** की शुरुआत।

जमीनों के रिकॉर्ड में पारदर्शिता लाने के लिए **WEB HALRIS** पूरे प्रदेश में लागू।

खनन ठेकों में **ई-नीलामी** और **ई-रवाना** स्कीम से पारदर्शिता।

डिजिटल साधनों से सेवाओं व योजनाओं का लाभ देने के लिए अलग से 'नागरिक संसाधन सूचना विभाग' का गठन किया।

आउटसोर्सिंग से जुड़ी सेवाओं में ठेका प्रथा बंद करने के लिए 'हरियाणा कौशल रोजगार निगम' बनाने का निर्णय लिया।

राज्य सरकार के कर्मचारियों से सम्बंधित सभी विषयों के लिए **मानव संसाधन विभाग** गठित।

व्यापारियों की सुविधा हेतु माल के अंतर्राज्यीय आवागमन के लिए **ई-वे बिल योजना**।

व्यवस्था परिवर्तन की प्रक्रिया में 'सरकार कम से कम-सुशासन अधिकतम' के भाव से सरकारी लाभ देने में मानवीय हस्तक्षेप को कम किया।

सुशासन की नई पहलों से प्रदेश के नागरिकों में यह भावना पैदा हुई है कि सरकार उनकी है और वे सरकार में हैं।

हरियाणा एक हरियाणवी एक





सरकार ने दूरदर्शिता से हरियाणा को क्षेत्रवाद और जातिवाद की अंधी गुफा से बाहर निकाला। अब “हरियाणा एक-हरियाणवी एक” सरकार का मूलमंत्र।

हरियाणा की राष्ट्रीय एवं वैश्विक पटल पर अपनी अलग पहचान है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भी प्रदेश के ओलंपिक खिलाड़ियों से बातचीत करते हुए कहा कि ‘हरियाणावासी अपनी जिंदादिली और खुशहाल जीवन जीने की कला के लिए प्रसिद्ध हैं।’

प्रदेश की अंतरराष्ट्रीय मानचित्र पर पहचान बनाने के लिए विदेशों में बसे हरियाणावासियों को अपनी मिट्टी से जोड़ने और उन्हें प्रदेश के विकास में भागीदार बनाने के लिए “विदेश सहयोग विभाग” बनाया गया।

सभी विधानसभा क्षेत्रों में समान विकास, हर जिले में मेडिकल कॉलेज तथा हर जिले में विश्वविद्यालय खोलने का लक्ष्य।

क्लस्टर एप्रोच के तहत सभी क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में विद्यालय, 20 किलोमीटर के दायरे में एक कॉलेज।

हर क्षेत्र की आर्थिक स्थिति की मजबूती के लिए ब्लॉक स्तर पर लघु व मध्यम उद्योगों के “क्लस्टर” स्थापित किए जा रहे।

माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा दिया गया विकास मंत्र ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास’ हमारा मार्गदर्शक भी हैं और नई नीतियों का केन्द्र बिन्दु भी।



स्वास्थ्य सेवाएं

“सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया”



प्रदेश में जन-जन को समुचित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध।

सभी सरकारी अस्पतालों एवं मेडिकल कॉलेजों में 500 दवाइयां और 228 प्रकार के ऑपरेशन मुफ्त।

हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने का लक्ष्य। इनकी संख्या 7 से बढ़कर 13 हुई। एमबीबीएस की सीटें 700 से बढ़कर 1685 कीं।

एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम में हरियाणा देश में प्रथम।

आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 3 लाख मरीजों का लगभग 383 करोड़ रुपये की लागत से मुफ्त इलाज।

कोविड-19 वैश्विक महामारी का टेस्ट, ट्रैक, ट्रेस व ट्रीट की नीति से नियंत्रण।

घर-द्वार पर मुफ्त चिकित्सा के लिए ई-संजीवनी ओ.पी.डी.।

कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान सड़क, रेल व हवाई मार्गों से लगभग 240 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की प्रतिदिन अतिरिक्त आपूर्ति एवं नए संजीवनी अस्पताल एवं स्वास्थ्य संस्थाओं में लगभग 10 हजार ऑक्सीजन/ICU बिस्तरों की अतिरिक्त व्यवस्था।



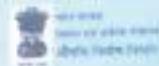


मोदी का जन्मांक प्रधान
मंत्री का जन्म के लिए जरूरी है।
जीवन में जन्मांक योग्य देश में
जन्म लेनी चाहिए ताकि वह संभवता हो।

प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केन्द्र

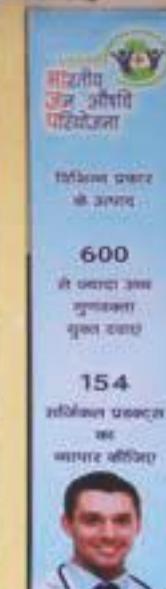


सरकारी योजना



भारतीय
जन औषधि
परियोजना

जन औषधि भाइकुण्ठ रोड



होम क्यारंटाइन मरीजों को घर पर ही 20,000 से अधिक ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाए।

गांव स्तर तक कोरोना टेस्टिंग के लिए 8000 टीमों का किया गठन।

कोविड-19 से ठीक होने वाले लोगों के लिए पी.जी.आई. रोहतक में 'पोस्ट कोविड केयर एंड रिसर्च सेंटर' स्थापित।

सभी कोरोना मरीजों का सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं में मुफ्त इलाज व सबका मुफ्त टीकाकरण।

बी.पी.एल. परिवार के कोरोना मरीजों का प्राइवेट अस्पतालों में भी मुफ्त इलाज, होम आइसोलेशन में रहे कोरोना मरीजों को 5-5 हजार रुपये एवं इन परिवारों के कमाने वाले सदस्य की कोरोना की मृत्यु होने पर दो लाख की आर्थिक सहायता।

हर गांव एवं शहर में 'हेल्थ एंड वैलनेस सेंटर' खोले जा रहे हैं। कोविड-19 महामारी ने हमें स्वास्थ्य के प्रति सचेत किया है। सब रोगमुक्त रहें, इसके लिए शैशवकाल से ही टीकाकरण के माध्यम से छोटी बीमारी से लेकर महामारी तक रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने का कार्य निरंतर जारी।

शिक्षा







प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सशक्त भारत के विजन को साकार करने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन की शुरुआत, वर्ष 2025 तक लागू करने का लक्ष्य।

बच्चों की नींव मजबूत करने के लिए पहली से कक्षा तीन तक **Functional Literacy and Numeracy (FLN)** कार्यक्रम की शुरुआत।

एक ही परिसर में केजी से पीजी तक शिक्षा। सत्र 2021-22 से कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया शुरू।

प्रदेश में 4,000 प्ले वे स्कूल खोलने का लक्ष्य, इनमें से 1135 प्ले वे स्कूल खोले गए।

प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर सुविधाएं और अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा देने के लिए 137 नये संस्कृति मॉडल स्कूल खोले।

1418 विद्यालयों में इंग्लिश मीडियम बैग फ्री विंग स्थापित।

नारियाणा FLN

नाननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के द्वारा

दिनांक ३० जुलाई २०२१

सभी को हार्दिक बधाई!

सरकारी स्कूलों के पहली से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें।

सुपर-100 कार्यक्रम के तहत सरकारी स्कूलों के ग्रामीण मेधावी विद्यार्थियों को मुफ्त कोचिंग।

कॉलेजों में युवाओं के कौशल प्रशिक्षण के लिए 'पहल योजना'।

डिजिटल पब्लिक लाइब्रेरी/ई-ग्रन्थकोष का शुभारंभ।

'उच्चतर शिक्षा परिषद' की स्थापना।

उच्चतर शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम में आसान शर्तों पर शिक्षा ऋण।

विदेशों में शिक्षा तथा रोजगार के अवसर तलाश रहे विद्यार्थियों के निःशुल्क पासपोर्ट।

कोविड-19 महामारी के दौरान विद्यार्थियों को शिक्षा सेतु ऐप, एजुसेट, Functional Literacy and Numeracy (FLN) व संपर्क बैठक ऐप के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा।

सुनारिया, रोहतक में Indian Institute of Management (IIM), कुरुक्षेत्र में National Institute of Electronics & Information Technology (NIEIT) और उमरी, कुरुक्षेत्र में उत्तर भारत का पहला National Institute of Design (NID) स्थापित।

मुरथल, सोनीपत में National Institute of Design (NID), पंचकूला में National Institute of Fashion Technology (NIFT) और किलोहड़, सोनीपत में National Institute of Fashion Technology (NIFT) स्थापित हो रहे।

IIT दिल्ली के दो विस्तार परिसर सोनीपत एवं झज्जर में स्थापित किये जा रहे।

खेलों में बेमिसाल हरियाणा







क्षेत्रफल एवं जनसंख्या के हिसाब से छोटे से राज्य हरियाणा के खिलाड़ियों ने टोक्यो ओलम्पिक में देश के आधे पदक जीते।

नीरज चोपड़ा ने 'ट्रैक एण्ड फिल्ड' खेलों में देश का पहला स्वर्ण, पहलवान रवि दहिया ने रजत व बजरंग पुनिया ने कांस्य पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया।

पुरुष हॉकी में कांस्य पदक जीतने वाली टीम में हरियाणा के दो खिलाड़ी सुमित कुमार व सुरेन्द्र कुमार तथा महिला हॉकी टीम में 9 खिलाड़ी शामिल।

हरियाणा के पदक विजेता खिलाड़ियों को **6 करोड़ रुपये** तक का देश में सर्वोच्च नकद पुरस्कार।

पिछले **2500 दिनों** में लगभग 12 हजार पदक विजेता खिलाड़ियों को 386 करोड़ रुपये के नकद ईनाम।

खिलाड़ियों को कॅरियर की चिंता से मुक्त करने के लिए उत्कृष्ट खिलाड़ियों को क्लास-1 का सरकारी पद।

खिलाड़ियों की प्रतिभा निखारने के लिए अर्जुन, द्रोणाचार्य व ध्यानचंद पुरस्कार विजेता कोच को 20,000 रुपये मासिक मानदेय।

तेनजिंग नोर्गे अवार्ड विजेताओं को 20,000 रुपये व भीम पुरस्कार विजेताओं को 5000 रुपये मासिक मानदेय।





पर्वतारोहियों को 5 लाख रुपये का नकद पुरस्कार और ग्रेड-सी खेल श्रेणी का प्रमाण-पत्र।

राई (सोनीपत) में 'हरियाणा खेल-कूट विश्वविद्यालय' की स्थापना की जा रही।

राज्य, ज़िला, खण्ड व ग्रामीण स्तर पर खेल परिसर बनाए।

नई खेल प्रतिभाओं को तराशने के लिए स्कूलों में 297 खेल नसरियाँ।

प्रदेश में खेलों का आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित। इसी के बल पर हरियाणा पहली बार करेगा फरवरी-2022 में 'खेलो इंडिया' की मेजबानी।

प्रगति की रफ्तार उद्योग व व्यापार







आर्थिक विकास एवं आजीविका के अवसर मुहैया करवाने तथा उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 'हरियाणा उद्यम एवं रोजगार नीति-2020' लागू।

5 लाख नौकरियों का सृजन तथा 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश का लक्ष्य।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई विभाग का गठन।

प्रदेश में ब्लॉक स्तर पर लघु व मध्यम उद्योगों के "क्लस्टर" स्थापित किए जाएंगे।

पिछले 2500 दिनों में 1,000 से अधिक बड़े व मध्यम तथा लगभग 2 लाख सूक्ष्म और लघु उद्यम स्थापित, जिनमें लगभग 50 हजार करोड़ रुपये का निवेश हुआ व 18 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिला।

सॉफ्टवेयर नियाति में हरियाणा देश में तीसरे स्थान पर।

'ईज ऑफ ड्रूंग बिजेस' में हरियाणा अग्रणी राज्यों में से एक।

प्रदेश के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक हब बनाया जा रहा।

फ्लिपकार्ट द्वारा 850 करोड़ रुपये का निवेश करने तथा इससे 13 हजार लोगों को रोजगार मिलने की संभावना।

'हरियाणा कृषि और खाद्य प्रसंस्करण नीति 2018' के तहत लगभग 200 करोड़ रुपये की कुल 15 परियोजनाओं को मंजूरी।

ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 'प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम' शुरू।



ग्रामीण क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यमों के लिए हरियाणा ग्रामीण उद्योग विकास योजना शुरू की गई।

उद्योगों की 'कॉस्ट ऑफ डुइंग बिजनेस' को कम करने के लिए औद्योगिक प्लाटों के लिए विशेष लीजिंग पॉलिसी।

युवाओं को उद्योगों की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण देने के लिए जल्द ही 'उद्योग मित्र योजना' शुरू।

वालमार्ट द्वारा पानीपत में 'वालमार्ट वृद्धि ई-इंस्टीट्यूट' शुरू।

उद्यमियों को एक ही छत के नीचे स्वीकृतियां प्रदान करने के लिए HEPC का गठन।

थोक व खुदरा व्यापारियों के कल्याण के लिए 'व्यापारी कल्याण बोर्ड' का गठन।

पंजीकृत, जी.एस.टी. करदाता छोटे व्यापारियों को आग और सेंधमारी आदि के नुकसान की भरपाई के लिए बीमा का लाभ दिया जाएगा।

लघु व मध्यम व्यापारियों के कल्याण को सक्रिय रूप से बढ़ावा देने के लिए उन्हें एम.एस.एम.डी. विभाग के अंतर्गत लिया गया।

रोजगार एवं कौशिल विकास





ITI
Industrial Training Institute

सक्षम
हरियाणा





युवाओं को रोज़गार के लिए सक्षम बनाना सरकार की प्राथमिकता।

पिछले 2500 दिनों में योग्यता के आधार पर 82,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां।

सरकारी पदों पर बार-बार आवेदन से व धन की, बचत के लिए 'एकल पंजीकरण' सुविधा।

बार-बार परीक्षा व समय की बचत के लिए 'कॉर्मन पात्रता परीक्षा'।

हरियाणा देश का पहला राज्य, जहां शिक्षित बेरोज़गार युवाओं को 'सक्षम युवा योजना' के तहत हर महीने 100 घण्टे काम की गारंटी।

प्रदेश के युवाओं को उद्योगों में रोज़गार के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण।

युवाओं के कौशल विकास एवं प्रशिक्षण के लिए 'प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना'।

युवाओं को स्वरोज़गार अपनाने व सक्षम बनाने हेतु 'श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय' स्थापित।

आधुनिक व्यवसायों के अनुरूप युवाओं को हुनरमंद बनाने के लिए 'हरियाणा कौशल विकास मिशन' गठित।

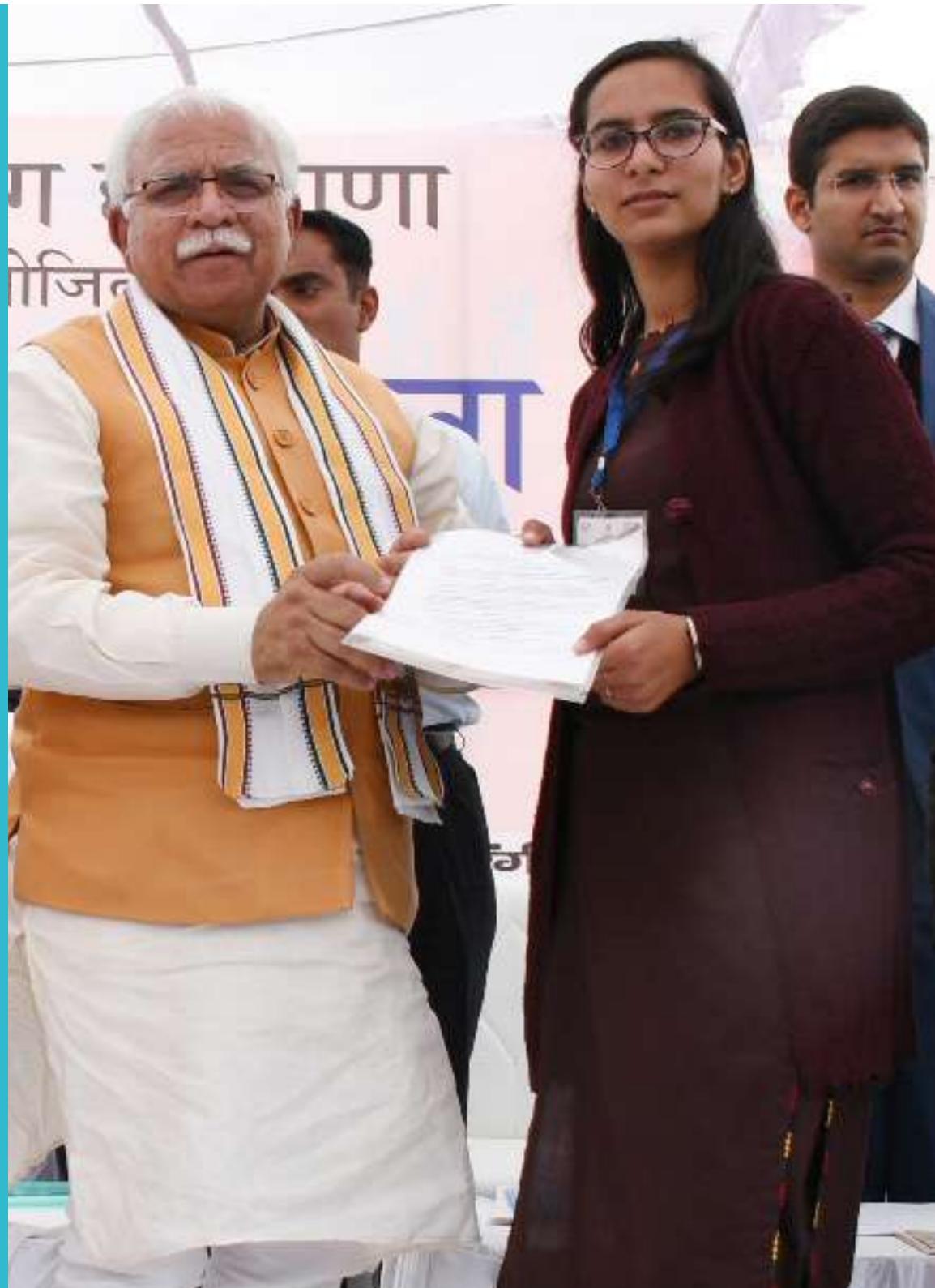
प्रति लाख जनसंख्या के आधार पर अधिकतम अप्रेंटिस लगाने के मामले में हरियाणा अग्रणी राज्य।

कौशल प्रशिक्षण के लिए स्कूलों में **National Skill qualification framework, पाठ्यक्रम**, कॉलेजों में पहल योजना और विश्वविद्यालयों में इन्क्यूबेटर सेंटर स्थापित।

'सक्षम हरियाणा अभियान' के तहत 80,000 युवाओं को ओला, उबर, जी4एस, जोमैटो और स्विगी में मिला रोज़गार।

तकनीशियन्स को रोज़गार उपलब्ध करवाने के लिए "मिस्त्री हरियाणा" पोर्टल व ऐप शुरू।

युवाओं को स्वरोज़गार के अवसर देने के लिए प्रदेश में 2,000 हर-हित स्टोर खोले जाएंगे। इनके अलावा 1718 पेट्रोल पंपों पर भी ये स्टोर खोले जाएंगे।



आधारभूत संरचना



प्रधानमंत्री

नरेन्द्र मोदी

द्वारा

स्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे के कुण्डली-मानेसर भाग

का



लंबी अवधि की बड़ी परियोजनाओं के लिए वर्ष 2021-22 में लगभग 8700 करोड़ रुपये का मीडियम टर्म “एक्सप्रेडिचर फ्रेमवर्क रिजर्व फंड” बनाया।

17 नए राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित, इनमें से 11 पर कार्य जारी। अब हर ज़िला जुड़ेगा राष्ट्रीय राजमार्ग से।

दिल्ली के चारों तरफ यातायात को सुगम करने के लिए कुंडली-मानेसर-पलवल और कुण्डली-गाजियाबाद-पलवल एक्सप्रेस-वे पर यातायात शुरू।

लगभग 30 हजार करोड़ रुपये की लागत से सराय कालेखां-पानीपत के बीच **Regional Rapid Transit System Connectivity** की परियोजना शुरू।

पलवल-सोनीपत और सोहना-मानेसर के लिए लगभग 6 हजार करोड़ रुपये की लागत से हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर मंजूर।

सोनीपत-जींद रेलवे लाइन पर यातायात शुरू।

रोहतक-महम-हांसी और करनाल-यमुनानगर रेलवे लाइन तथा कुरुक्षेत्र में एलिवेटेड रेलवे लाइन का कार्य शुरू।



43 रेलवे उपरिगामी पुल/रेलवे भूमिगत पुलों का निर्माण कार्य पूर्ण तथा 56 का कार्य प्रगति पर।
सोनीपत के बड़ी में 161 एकड़ भूमि पर रेल कोच रिपेयर फैक्टरी लगाई जा रही।

मुंडका-बहादुरगढ़, वार्ड.एम.सी.ए. चौक फरीदाबाद-बल्लभगढ़, सेक्टर-56, गुरुग्राम-
सिकंदरपुर व बदरपुर-मुजेसर मेट्रो रेल सेवा शुरू तथा नरेला से कुण्डली, सोनीपत तक दिल्ली
मेट्रो विस्तार को मंजूरी।

हिसार में बना प्रदेश का पहला एयरपोर्ट।

'उड़ान स्कीम' के तहत चंडीगढ़-हिसार एयर टैक्सी सेवा शुरू।

खेतों में आवाजाही को सुगम बनाने के लिए पांच करम के सभी रास्तों को पक्का किया जा रहा।

मेवात क्षेत्र में भू-जल संरक्षण, पेयजल व सिंचाई के लिए कोटला झील के पुनरुद्धार का 90
प्रतिशत कार्य पूर्ण।

पूरे राज्य में बिजली की हर समय आपूर्ति सुनिश्चित की। 'म्हारा गांव-जगमग गांव योजना' में 76
प्रतिशत गांवों में 24 घण्टे बिजली।

33 के.वी. के 179 नये सब-स्टेशन स्थापित व 449 सब-स्टेशनों की क्षमता में वृद्धि तथा लगभग 2000
किलोमीटर लम्बी 33 के.वी. की सम्प्रेषण लाइनें बिछाईं।

प्रदेश में 1.25 लाख नये ट्रांसफार्मर लगाए गए।

बिजली वितरण कम्पनियों के लाइन लॉसेस 30.3 प्रतिशत से घटकर हुए 17.27 प्रतिशत।

प्रदेश में 215 नहर व 116 नलकूप आधारित जलधर स्थापित, पेयजल बढ़ोत्तरी के लिए लगभग 3 हजार
नलकूप तथा 722 बूस्टिंग स्टेशन शुरू, लगभग 16 हजार किलोमीटर लम्बी पेयजल पाइप लाइनें बिछाईं
और 76 मल शोधन संयंत्र किये स्थापित।

'अमृत योजना' के अन्तर्गत एक लाख से अधिक आबादी वाले 20 शहरों में जलापूर्ति, ड्रेनेज, पार्क और
सीवरेज के लिए लगभग 2500 करोड़ रुपये की लागत के कार्य।

करनाल, गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकूला को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा तथा और भी नई स्मार्ट
सिटीज बनाई जायेंगी।

बड़े शहरों के समग्र विकास के लिए गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकूला में मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट
अथारिटी स्थापित।

गुरुग्राम, फरीदाबाद और करनाल में सिटी बस सेवा शुरू की गई। अन्य शहरों में भी इसे शुरू
किया जाएगा।



उद्घाटन
समाप्ति

पर्यावरण संरक्षण





हर जिला मुख्यालय पर 'ऑक्सी वन' स्थापित होंगे।

75 साल से अधिक आयु के वृक्षों की विशेष देखभाल के लिए 'प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम' के तहत 2500 रुपये प्रति वर्ष प्रति पेड़ पेंशन का प्रावधान।

किसानों को खेत में वृक्ष लगाने पर 'ऑक्सीजन खेती' मानते हुए 3 साल तक प्रति एकड़ प्रतिवर्ष 10 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि।

नरसी से पौधों के मुफ्त वितरण के लिए 'ई-पौधशाला' मोबाइल ऐप शुरू।

प्रदेश में 60 नए हर्बल पार्क विकसित।

प्रदेश को हरा-भरा बनाने के लिए 'हर गांव पेड़ों की छांव', 'हर घर हरियाली' तथा 'पौधगिरी' जैसी योजनाएं सफलतापूर्वक चलाई।

प्रदेश के दो Wetland sites - सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, गुरुग्राम व भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य, झज्जर को Ramsar site के रूप में अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली।

प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाए गए 'कचरे से कंचन' अभियान को गति देने के लिए गुरुग्राम में डीजल ऑटो को स्कैप कर उसके स्थान पर ई-ऑटो चलाए जाएंगे।

सोनीपत के मुरथल में 177 करोड़ रुपये की लागत से कूड़े-कचरे से बिजली उत्पादन संयंत्र स्थापित।



जल संरक्षण



खपानी-मेवी विचास्त

“ धान की फसल से मिलने वाला धन तो पानी की तरह बह जाता है, परंतु धान उगाने में लगने वाला भू-जल कभी वापिस नहीं आता। धान उगाने के चक्कर में अपनी आने वाली पीढ़ियों के पानी जैसे अमूल्य धन को बर्बाद न करें। ”

-मनोहर लाल मुख्यमंत्री हरियाणा



डों (रतिया, सिराहा, गोत्ता, पिपली, झाहवाद, बबैन
वे गाँव जिनका दूरी स्तर 40 मीटर व अधिक है वहाँ
फसलों (भू-वाजरा/दलहन/सब्जियाँ
क्षेत्र में नी सलाह दी जाती है।

पर्ये प्रति एकड़

पर्ये प्रति एकड़

पर्ये प्रति एकड़

पर्ये प्रति एकड़

में 50 एक.पी. सोटी के विजली करेक्षण वाले
को धान न लगाने सलाह दी जाती है।

इम्माइलनावाद, भीवन
होवा, फतेहाबाद
पर पूर्ण प्रतिशत

1

जल संरक्षण के लिए **Reduce, Recycle व Reuse** की नीति पर काम।

जल संरक्षण और फसल विविधिकरण के लिए “मेरा पानी-मेरी विरासत” योजना शुरू।

गंदे पानी का सदुपयोग करने के लिए **ट्रीटेड वेस्ट वॉटर पॉलिसी** बनाई।

“जल बचाओ-कल बचाओ” योजना के तहत हरियाणा के 200 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स से 700 क्यूसेक ट्रीटेड वेस्ट वॉटर का पावर प्लांट्स व उद्योगों में किया जा रहा उपयोग।

“सूक्ष्म सिंचाई से हर खेत में पानी” योजना के तहत 600 करोड़ रुपये की लागत से महेंद्रगढ़, चरखी-दादरी, भिवानी और फतेहाबाद ज़िलों के 9 एस.टी.पी. से उपयोगित जल का सिंचाई के लिए उपयोग।

पानी के संरक्षण, प्रबंधन, पुनः उपयोग, रिचार्ज और रिसाइक्लिंग के लिए वर्ष 2021-23 को ‘जल द्विवार्षिक’ के रूप में मनाने का निर्णय।





नालों में रिसाव से पानी की बबादी रोकने के लिए 3700 करोड़ रुपये की लागत से 1,546 रजवाहे होंगे पक्के। 20 साल से अधिक पुराने रजवाहों को भी किया जाएगा दोबारा पक्का।

प्रधानमंत्री जी की '**Per Drop-More Crop**' अवधारणा के तहत सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियों पर 85 प्रतिशत सब्सिडी।

Haryana Water Resources Authority, MICADA और **Haryana Pond and Waste Water Management Authority** का गठन।

बागवानी फसलों की सूक्ष्म सिंचाई के लिए जल संग्रहण तालाब बनाने पर 7 लाख रुपये तक अनुदान।

प्रत्येक गांव का बनेगा जल उपलब्धता सूचकांक।

'जल जीवन मिशन' के तहत 'हर घर नल से जल' योजना के तहत आठ ज़िलों के सभी ग्रामीण घरों में जल आपूर्ति कनेक्शन।

सरक्त एवं आत्मनिर्भर स्थानीय निकाय



तौसर को नगर निगम बनाये जाने पर

मनोहर लाल

य मुख्यमंत्री, हरियाणा

क आभार एवं अभिनन्दन

धीर, वर शाम, तौसर थोड़े



अंतरराज्यीय परिषद् की तर्ज पर अंतर ज़िला परिषद् का गठन करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य।

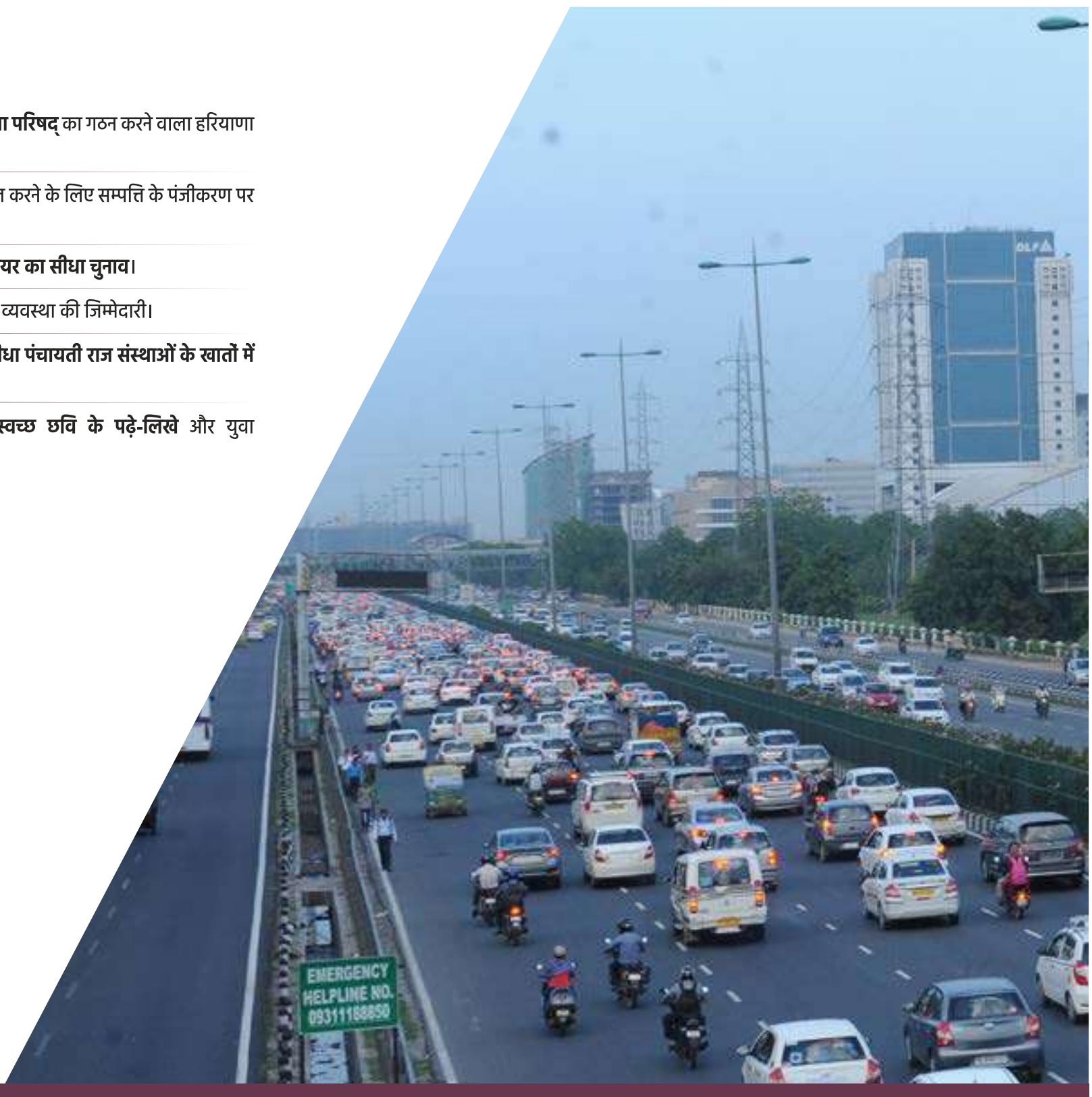
स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति मजबूत करने के लिए सम्पत्ति के पंजीकरण पर 2 प्रतिशत राजस्व प्रदान किया गया।

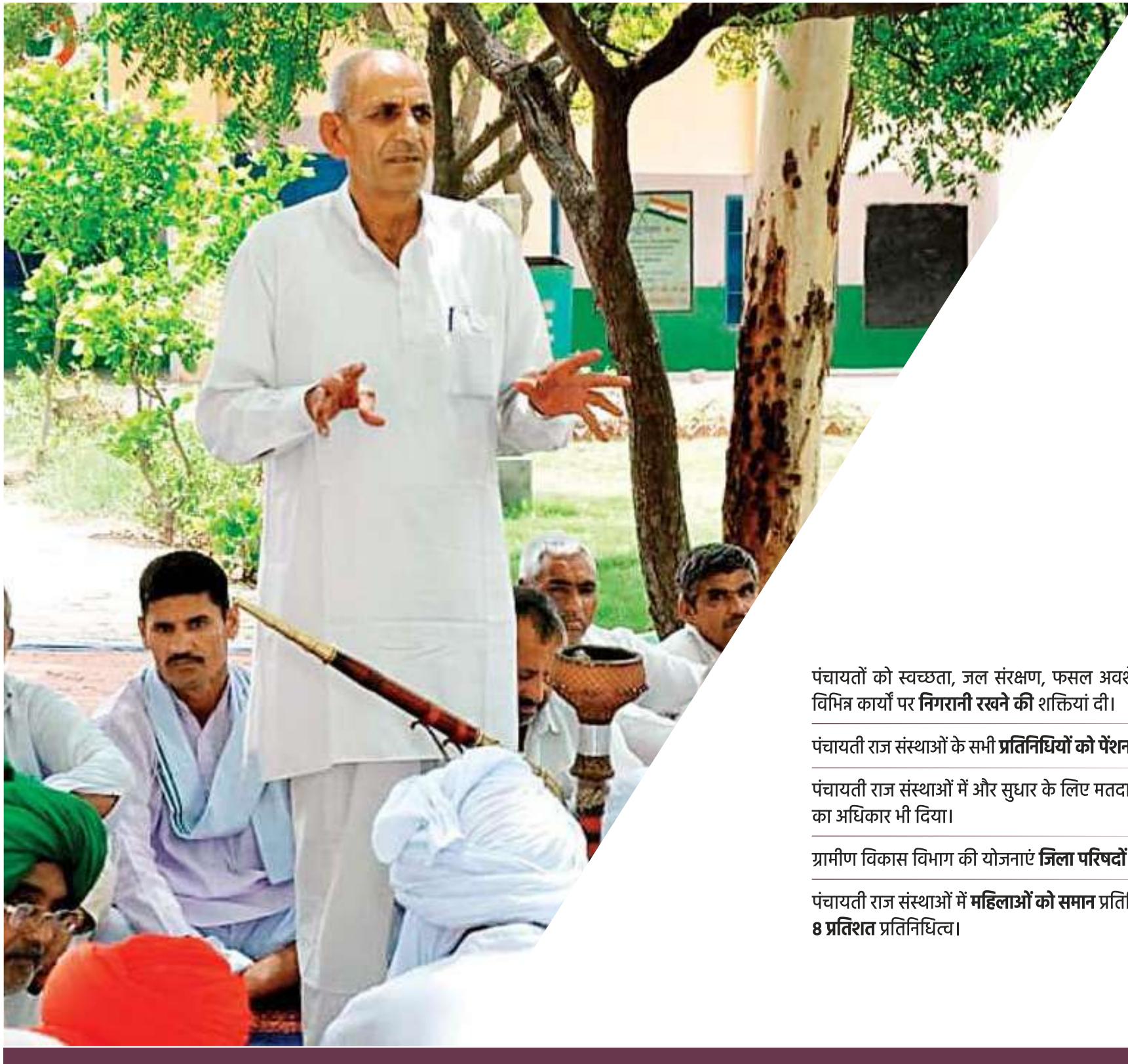
शहरी निकायों को मजबूत करने के लिए मेयर का सीधा चुनाव।

नगर निगमों को पेयजल आपूर्ति व सीवरेज़ व्यवस्था की जिम्मेदारी।

राज्य और केंद्रीय वित्त आयोग का पैसा सीधा पंचायती राज संस्थाओं के खातों में दिया जा रहा।

प्रदेश की पंचायती राज संस्थाओं में स्वच्छ छवि के पढ़े-लिखे और युवा जन-प्रतिनिधि।





पंचायतों को स्वच्छता, जल संरक्षण, फसल अवशेष जलाने में कमी लाने जैसे विभिन्न कार्यों पर निगरानी रखने की शक्तियां दी।

पंचायती राज संस्थाओं के सभी प्रतिनिधियों को पेंशन देकर उनका सम्मान बढ़ाया।

पंचायती राज संस्थाओं में और सुधार के लिए मतदाताओं को **Right To Recall** का अधिकार भी दिया।

ग्रामीण विकास विभाग की योजनाएं जिला परिषदों को हस्तांतरित।

पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को समान प्रतिनिधित्व और बी.सी.ए. वर्ग को 8 प्रतिशत प्रतिनिधित्व।

महिला एवं बाल कल्याण









‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ कार्यक्रम के फलस्वरूप प्रदेश में जन्म के समय लिंगानुपात की दर वर्ष 2014 में 871 से सुधरकर अब 911 हो गई।

महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में **50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व।**

कोविड के कारण अनाथ हुए बच्चों के पुनर्वास और सहायता के लिए ‘मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना’ शुरू।

500 नए मॉडल क्रेच खोलने का काम शुरू।

‘महिला एवं किशोरी सम्मान योजना’ के तहत बी.पी.एल. परिवारों की किशोरियों व महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन।

‘प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना’ के तहत 9.19 लाख मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन दिये।

‘छात्रा परिवहन सुरक्षा योजना’ के तहत 6000 से अधिक विशेष वाहन चलाए।

प्रदेश में 31 महिला पुलिस थाने स्थापित। महिलाओं की सुरक्षा के लिए ‘शक्ति ऐप’, ‘दुर्गा शक्ति वाहिनी’, ‘दुर्गा शक्ति रैपिड एक्शन फोर्स’ की स्थापना।

महिलाओं के विरुद्ध अपराध के मामलों की तेजी से सुनवाई के लिए **16 फास्ट ट्रैक कोर्ट** स्थापित।

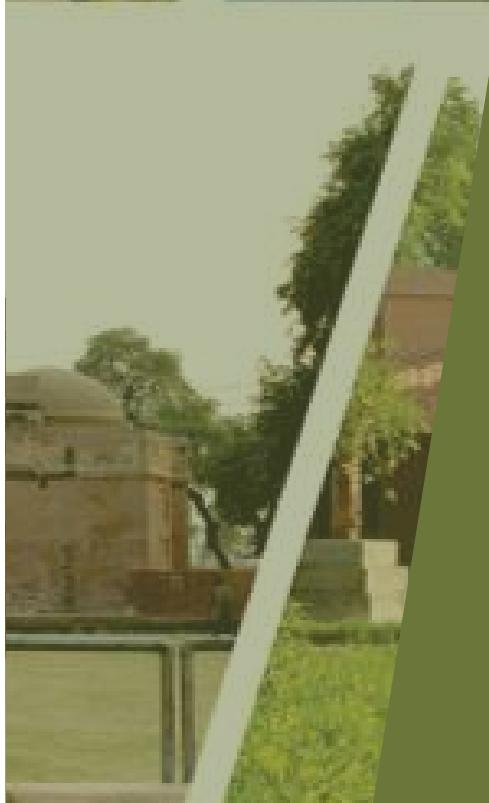
यौन हिंसा से लेकर घरेलू हिंसा का शिकार महिलाओं के लिए सभी जिलों में वन स्टाप सेंटर ‘सखी’ शुरू।

सभी बस अड्डों व 400 सामान्य बसों में सीसीटीवी कैमरे लगाये गये।

महिलाओं की सुरक्षा और सुगमता के लिए **पिंक कलर की बसें** चलाई।



कला, संस्कृति, पर्यटन एवं पुरातत्व







राखीगढ़ी में 6 एकड़ क्षेत्र में संग्रहालय एवं विवेचन केन्द्रों का निर्माण कार्य ज़ोरों पर।

“प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857” के शहीदों के सम्मान में अम्बाला छावनी में 22 एकड़ क्षेत्र में शहीदी स्मारक निर्माणाधीन।

भारतीय संस्कृति को संरक्षित करने और आने वाली पीढ़ियों को अपनी समृद्ध परम्पराओं से अवगत कराने के लिए कुरुक्षेत्र में हर साल अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन।

पावन सरस्वती नदी को पुनः धरा पर लाने और इसके तटों पर स्थित तीर्थों के जीर्णोद्धार के लिए सरस्वती विकास बोर्ड का गठन।

लोहगढ़ की ऐतिहासिक, धार्मिक व सांस्कृतिक विरासत को संजोने के लिए बाबा बंदा सिंह बहादुर ट्रस्ट की स्थापना।

धार्मिक स्थलों की यात्रा के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान।

कला एवं सांस्कृतिक विरासत को प्रोत्साहन देने के लिए ‘राज्य कला नीति’ लागू।

हरियाणा में फिल्म निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए हरियाणा फिल्म पॉलिसी लागू।

फिल्म बनाने की सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए पिंजौर में फिल्म सिटी विकसित करने का निर्णय।

पंचकूला को टूरिज्म हब के रूप में विकसित करने के लिए मोरनी में एडवेंचर स्पोर्ट्स, टूरिज्म सर्किट रूट, माउटेन ट्रेल, माउटेन-बाइकिंग और पैराग्लाइडिंग सुविधाओं को विकसित किया गया।

विवादों का समाधान





हरियाणा सरकार

ल डोरा मुक्त गांव सिरसी में टाईटल



हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP), हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास निगम (HSIIDC), हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड (HSAMB), नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग आदि के ब्याज, पैनल ब्याज, वैट व जीएसटी विवादों, परिवहन करों, खनन बकायों, और स्टाम्प झूटी जैसे सरकारी बकायों व अन्य विवादों के निपटान के लिए 'विवादों का समाधान' शुरू किया गया।

गांवों में मालिकाना हक से सम्बन्धित विवादों पर अंकुश लगाने के लिए लाल डोरा मुक्त करने की योजना शुरू की गई, जिसे बाद में प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के नाम से पूरे देश में लागू किया गया। शहरों के लाल डोरा की भूमि को भी किया शामिल।

20 साल से अधिक समय से किराये या लीज अथवा लाइसेंस फीस पर चल रही पालिकाओं की दुकानों व मकानों की मिल्कियत उन पर काबिज व्यक्तियों को ही देने का निर्णय।

लोगों की समस्याओं और शिकायतों का समाधान करने के लिए 'सी.एम. विन्डो' पोर्टल के माध्यम से 8 लाख से अधिक समस्याओं व शिकायतों का किया समाधान।





